LOK SABHA

Friday, December 15, 1967/Agrahayana 24, 1889 (Saka)

(The Lok Sabha met at Eleven of the Clock)

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रत्नागिरी में अल्यूमीनियम कारखाना

*691. **श्री बसवन्त** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रत्नागिरि में स्थापित होने वाले अल्यूमीनियम कारखाने में कितनी पूंजी लगाई जायेगी, उसका उत्पादन कार्यक्रम क्या है और उसमें कितने व्यक्तियों के नियुक्त किये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु गठित समिति ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है; और

(ग) इस समय परियोजना किस स्थिति में है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) रत्नागिरि (महाराष्ट्र) में जो परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है उस पर आने वाली लागत पूंजी का भारत एल्यूमीनियम कम्पनी जिन्होंने इसको कार्यान्वित करना है ने 68.88 करोड़ रुपये (नगर बसाने के लिए 4.55 करोड़ रुपये अतिरिक्त) का अस्थाई अनुमान लगाया है। परियोजना की 50,000 टन प्रति वर्ष एल्यूमीनियम धातु बनाने की क्षमता होगी, (जिस में 25,000 टन विद्युदांशिक श्रेणी के एल्यूमीनियम तार छड़ें, 10,000 टन मिश्रित धातु और 15,000 टन एल्यूमीनियम पिंडक शामिल हैं)। साथ ही स्फोदिज खनन और उससे एल्यूमिना निकालने की सहायक सुविधाएं भी होंगी। पश्चिमी जर्मनी के परामर्श-दाताओं द्वारा बनाए गए अस्थाई, अनुमान के अनुसार, चालन अवस्थ में परियोजना पर सम्भवतः लगभग 2,000 व्यक्ति लगाए जायेंगे जिनमें कार्यकर्ता, देख-भाल करने वाले, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी भी शामिल हैं।

(ख) सितम्बर, 1964 में तकनीकी अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने प्रस्तावित एल्यूमीनियम परियोजना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान के प्रश्न का अध्ययन किया। पश्चिमी जर्मनी के परामर्शदाताओं के साथ बातचीत करने के बाद परियोजना को रत्नागिरि में स्थित करने का निर्णय किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने आम तौर से रत्नागिरि (महाराष्ट्र) एल्यूमीनियम परियोजना को कार्यान्वित करने का निश्चय कर लिया है और इस समय परियोजना के उन पहलुओं पर फिर से विचार कर रही है जिनका सम्बन्ध मुख्यतः देशी उपकरण और सेवाओं का अधिकाधिक प्रयोग करने से है।

श्री बसवन्त : यह रत्नागिरि परियोजना बहुत साल से चल रही है अभी तक वह कार्यान्वित नहीं हो पाई है मगर अभी जो जवाब दिया है उसको पढ़ने से पता चलता है कि

यह रत्नागिरि में अल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना का काम सरकार आरम्भ करने वाली है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की लागत क्या होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): इस बारे में कई साल से जांच हो रही है यह बात सही है लेकिन इस सम्बन्ध में वैस्ट जर्मन कंसलटेंट्स से डिस्कशन करने के बाद टैक्निकल आफिसर्स की कमेटी से जो रिपोर्ट मिली है और जिसने कि इस अल्यूमीनियम प्रोजैक्ट के लिए सूटेबुल लोकैशन के बारे में जांच पड़ताल की है उसके फलस्वरूप रत्नागिरि में यह कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया गया है। हम यह भी देख रहे हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा इस काम में हम इंडिजनस इक्विपमेंट और सर्विसेज काम में ला सकते हैं ? इसकी पूरी कौस्ट प्रौविजनली 68.88 करोड़ रुपये प्लस 4.55 करोड़ रुपये फौर दी टाउनशिप अंदाजी गई है। इस प्रोजैक्ट में स्टेट गवर्नमेंट की कोई आर्थिक मदद नहीं है।

श्री बसवन्त: अभी मंत्री महोदय ने कहा कि भारत सरकार की अधिक से अधिक देशी उपकरण और सेवाओं का प्रयोग करने की कोशिश है और नीति है तो अगर समय पर यह देशी उपकरण आदि उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या परियोजना को स्थगित किया जायेगा ?

डा० चन्ना रेड्डी: यह सही बात है कि हम अपने देश के अन्दर जो खुद उपकरण आदि तैयार कर सकते हैं उनका अधिक से अधिक इस प्रोजैक्ट में उपयोग करने की हमारी पालिसी है और उस दिशा में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, गुजिश्ता हफ्ते में जांच की भी थी और उम्मीद है कि एक, दो हफ्ते में यह जांच पूरी हो जायगी।

श्री जार्ज फरनेन्डीज: अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के 469 नम्बर पेज पर इस रत्नागिरि प्रोजैक्ट के बारे में यह लिखा गया था :

"The target of 87,500 tonnes set for 1965-66 is to be achieved as a result of the following projects in the private sector which have already been cleared for implementation. . ."

और उसमें तीन नम्बर हैं।

"establishment of a smelter at Koyna of 20,000 tonnes annual capacity. . ."

आगे जाकर यह चौथी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 263 नम्बर पन्ने पर यह लिखा है :

"The public sector schemes included in the Fourth Plan are : the Koyna aluminium project with a capacity of 50,000 tonnes . . ."

अब अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही प्रश्न है। एक तो खैर इनकी कोई कीमत नहीं है यह तो 5 साल में एक बार पेश करते और लाइब्रेरी में फिर रख देंगे। यह उसका काम है मैं समझ सकता हूं लेकिन मुझे यह जवाब चाहिए कि जब वहां एक जमाने में प्राइवेट सैक्टर के हाथ में यह प्रोजैक्ट को आगे बढ़ाने का आप ने फैसला किया तो कुछ शुरूआत का काम भी हो गया था तो कब आप ने यह फैसला किया कि प्रोइवेट सैक्टर से हटा कर इसको पब्लिक सैक्टर में दिया जाय और जब आप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इस के लिए सितम्बर '64 में टैकनिकल आफिसर्स की एक कमेटी बना दी गई थी तो उसको बने हुए अभी तीन साल हो गये तो तीन सालों में पब्लिक सैक्टर में लेकर इस काम को आगे बढ़ाने में क्यों देरी हो रही है ?

डा० चन्ना रेड्डी: चीज यह है कि टेंदूलकर एंड कम्पनी जो एक प्राइवेट कम्पनी थी उस ने चार साल काम किया लेकिन इन चार सालों तक काम करते-करते उसका कोई नतीजा न

आने पर केन्द्र सरकार ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, पब्लिक सैक्टर में ले लिया और इस प्रोजैक्ट का इम्लीमेंटेशन भारत अल्यूमीनियम कम्पनी को सौंप दिया। इसके साथ ही हमने सितम्बर 64 में इसके लिए टैकनिकल आफिसर्स की एक कमेटी सैटअप कर दी जिसने कि वैस्ट जर्मन कंसलटैंट्स से इस बारे में सलाह मशविरा करके सन् 1965 में रिपोर्ट दी फिर इस बारे में काफी आपस में एखतलाफ रहा कि यह कारखाना किस जगह पर लोकैट किया जाय फिर सन् 1966 में आखिरी तौर पर यह निर्णय लिया गया कि रत्नागिरि में यह कारखाना स्थापित किया जायेगा। उसके बाद से टैकनिकल इक्विपमेंट कितना वहां से लेना जरूरी है इस पर सलाह मशविरा किया और यह दो महीने पहले हो भी गया था मगर वैस्ट जर्मनी ने इस बात पर इसरार किया है कि कितना इंडिजनस इक्विपमेंट होना चाहिए आखिरी फैसला करना यह उनके अधिकार में होना चाहिए लेकिन उसे हमने स्वीकार नहीं किया है और हम अभी इस बात की जांच कर रहे हैं कि हम अपने वहां का इंडिजनस इक्विपमेंट जितना भी अधिक मुमकिन हो इस्तेमाल करें।

श्री देवराव पाटिल : यह परियोजना प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त स्थान का प्रश्न अध्ययन करने के वक्त क्या इस समिति ने विदर्भ में एक स्थान का सुझाव दिया था और दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह देशी उपकरण और विदेशी उपकरण जोकि इस प्रोजैक्ट में इस्तेमाल होने हैं उनका ब्योरा क्या है ?

डा० चन्ना रैड्डी : इस कारखाने की स्थापना करने के लिए तीन चार जगहों के बारे में अध्ययन किया गया जहां पर कि इस को स्थापित किया जा सकता है और जिन जगहों के लिए सुझाव दिया गया वह थीं जयगढ़, पैडम्बी, तकारी, कोल्हापुर, देवरुख और रत्नागिरि। इन 6 जगहों पर जांच पड़ताल करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इसके लिये सब से ज्यादा रत्नागिरि अच्छा रहेगा क्योंकि वहां पर दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। इस 68.88 करोड़ की टोटल कौस्ट वाले प्रोजैक्ट के लिए अनुमान किया जा रहा है कि 18 करोड़ का सामान हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा मैं मानता हूं कि यह ज्यादा है और जितना हम उसे कम कर सकते हैं उसको कम करने के बारे में विचार कर रहे हैं ?

श्री रवि राय : क्या यह सत्य नहीं है कि विशेषज्ञों ने पहले ही भारत सरकार को पब्लिक सैक्टर में इस फैक्टरी को बनाने का सुझाव दिया था लेकिन चूंकि मंत्री महोदय ने उस सुझाव को नहीं माना इसलिए उस फैक्टरी को बैठाने में इतना विलम्ब हुआ, इतनी देर हुई ?

डा० चन्ना रैड्डी : माननीय सदस्य ने जिन विशेषज्ञों का हवाला दिया कि इसे पब्लिक सैक्टर में बनाया जाय तो उन के विचार यह थे:

"This is a remote and under-developed area; it will be difficult to create nnecessary infra-structure; the limited water potential inhibits further expansion of the plan . . ."

यह उन की रिपोर्ट है इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि मिनिस्टरी ने उसको पहले ऐसे ही रिजैक्ट कर दिया था।

श्री तुलशीदास जाधव : क्या इस परियोजना के बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ राय बताई है कि इसे रत्नागिरि में स्थापित करने में ज्यादा सहूलियत है और यह इंडिजनस मैटीरियल वहां पर अपेक्षाकृत अधिक सुलभ हैं ? इस बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की क्या राय है ? क्या उनकी राय आपने ली है ?

डा० चन्ना रैड्डी : महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रिप्रजेंटेटिवस को भी हमने बराबर उस कमेटी में रखा और उनकी पहली रैकमेंडेशन देवरुख या पैडम्बी के बारे में थी लेकिन बाद में जब वह जर्मन ऐक्सपर्टस मैदान में आये और उनके भी विचार सुने गये तो आमतौर पर इस कारखाने के लिए उस कमेटी द्वारा रत्नागिरि को ज्यादा मौजूं पाया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या यह बात सही है कि कुछ देश ऐसे हैं कि जब उनके साथ कोलैबरेशन किया जाता है पब्लिक सैक्टर में तो इस बात पर वह जोर डालते हैं कि वह हमारे देश का जो इंडिजनस इक्विपमेंट है और मैटीरियल एवेलेबुल है उस को इस्तेमाल न करके वह अपने देश के इंडिजनस इक्विपमेंट, मैटीरियल और नोहाऊ को युटिलाइज करने के लिए हम से इंसिस्ट करते हैं, यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उनकी इस डिमांड को मान लिया है और क्या ऐसा मानना सरकार के लिए सही पालिसी है? क्या वैस्ट जर्मनी इस बात पर जोर डाल रहा है कि हमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये तो क्या भारत सरकार ने इस बीच में दूसरे किन्हीं देशों से इस बारे में निगोशिएट करना उचित समझा है ताकि हम अपने देश की ही क्षमता को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा अच्छी शर्तों पर ऐसे दूसरे देशों से कोलैबरेशन करके इस फैक्टरी को लगाया जाय ?

डा० चन्ना रेड्डी : किसी अन्य देश के बारे में आम तौर पर कोई इस तरह से पबलिक्ली खयाल जाहिर करना मुश्किल है और वह ठीक भी नहीं है। वैस्ट जर्मनी वालों की यह राय है और उन्होंने हम को आश्वासन दिया है कि जहां तक मुमकिन हो सकेगा हम इस देश के इंडिजनस इक्विपमेंट का ही उसमें इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल अभी फाइनल डिसीशन होना शेष है और गवर्नमेंट देखेगी कि इस देश का ज्यादा से ज्यादा इंडिजनस इक्विपमेंट उसमें इस्तेमाल किया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव: मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल यह था अगर कि वैस्ट जर्मनी इस बात को नहीं मानता है और इस वजह से प्रोजैक्ट का काम रुकता है तो क्या सरकार किसी और देश के साथ इस बारे में बातचीत कर रही है या उसने की है कि हमारी शर्तों को मान कर इस फैक्ट्री के काम को आगे बढ़ाया जाए।

डा० चन्ना रेड्डी : अभी वह स्टेज नहीं आई है। बातचीत चल रही है। हम देख रहे हैं कि एन० आई० डी० सी० कितना काम कर सकती है। इसके बाद अगर वैस्ट जर्मनी वाले मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर उस बात को सोचने का सवाल उठेगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : आज ही के अखबारों में यह खबर आई है कि भोपाल हैवी इलैक्ट्रिकल्ज, बैलगांव में एल्यूमीनियम का जो कारखाना स्थापित होने जा रहा है उसको दो करोड़ का माल देगा। क्या यह सच है और क्या इसको सीमा विवाद के कारण खटाई में तो नहीं डाल दिया जाएगा ?

MR. SPEAKER : That has nothing to do with this. Next question.

SHRI R. BARUA : Question 697 may also be taken up with this.

MR. SPEAKER : Yes.

COTTON TEXTILE EXPORT PROMOTION SCHEME

*692. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the Pre-devaluation cotton textile export promotion scheme was originally meant for cotton goods;

(b) whether by a subsequent notification/rule/circular it was decided to bring ready-made clothes within the purview of the scheme;

(c) whether makers of ready-made garments were notified about the extension of the scheme to their trade through announcement in the Official Gazette or in newspapers;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the names of the makers of ready-made clothes who received incentive payments and the extent of the benefits received by them ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) and (b), Yes, Sir.